राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(A)(23)आर.बी./2024/4003 दिनांक :24 जुलाई, 2025

—: कार्यवाही विवरण :—

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2025 को प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 01:00 तक राजभवन जयपुर में प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित में NAAC Ranking एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान से लागू करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

1. बैठक राष्ट्रगान के साथ प्रारम्भ हुई एवं इसके पश्चात् सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से NAAC रैंकिग से सबंधित पीपीटी प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध किया गया।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा NAAC की आवश्यकता एवं NAAC रैंकिग प्राप्त किये जाने के बिन्दुओं से अवगत करवाते हुए एवं राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों/कार्मिकों की रिक्तियों एवं आधारभूत संरचनाओं के अभाव में तथा कुछ विश्वविद्यालय नये होने के कारणों का उल्लेख करते हुए, साथ ही कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा NAAC रैंकिग के संबंध में की जा रही प्रगति से अवगत करवाते हुए NAAC रैंकिग से सबंधित PPT का प्रस्तुतिकरण किया गया (**संलग्नक–1**)।

3. कुलपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ अजमेर द्वारा NAAC रैंकिग के संबंध में निम्नानुसार अवगत कराया गयाः—

   - माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 29 जुलाई, 2025 को NAAC Basic Accreditation का शुभारम्भ किया जायेगा,
   - NAAC Basic Accreditation हेतु शिक्षकों एवं आधारभूत संरचना की कमी के बावजूद भी विश्वविद्यालय NAAC Basic Accreditation प्राप्त कर सकता है।
   - एक विश्वविद्यालय दो बार NAAC Basic Accreditation प्राप्त कर सकता है।
   - NAAC Basic Accreditation हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा कुछ रिपोर्ट चाही जाती है, केवल रिपोर्ट के आधार पर भी NAAC Basic Accreditation प्राप्त किया जा सकता है।

4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि आज के परिप्रेक्ष्य में देश के विकास एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में Skill Based पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण कारक माना जाकर शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। प्रदेश में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय एक मात्र

Skill Based विश्वविद्यालय है, परन्तु विश्वविद्यालय में कुलसचिव सहित नियमित शिक्षकों/कार्मिकों के पद रिक्त है, साथ ही विश्वविद्यालय का स्थायी भवन आज दिनांक तक तैयार नहीं हुआ है, जिसके कारण विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय NAAC रैंकिग के आवेदन हेतु पात्र नहीं है।

5. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा NAAC रैंकिग पोर्टल पर Account बना दिया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय को एक्सीलेन्सी सेन्टर हेतु 45 करोड़ रूपयें प्राप्त हुए है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे है तथा वर्ष 2026 में NAAC रैंकिग प्राप्त किये जाने का प्रयास कर रहे है।

6. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मेडिकल कॉलेज जोधपुर एवं बाड़मेर में MBBS पाठयक्रम हिन्दी में प्रारम्भ किया गया है, इन दोनों महाविद्यालयों में हिन्दी पाठ्यक्रम लागू करने के गुणावगुण के आधार पर अन्य महाविद्यालयों में हिन्दी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विचार किया जायेगा।

   विश्वविद्यालय में 96 प्रकार के शिक्षकों की भर्ती होती है, वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 45% पद रिक्त है, उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु तेज गति से प्रयास करने होंगे, इस हेतु सुझाव दिया गया कि भर्तियों में साक्षात्कार को वैकल्पिक कर देना चाहिए जिसके लिए विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है।

7. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में डीन कमेटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम लागू किया जाता है।, ICAR द्वारा आधारभूत संरचना तैयार करवाई जाती है, साथ ही सुझाव दिया गया कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में NAAC रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय को परामर्शदात्री (Mentor) कमेटी के गठन हेतु आग्रह किया गया।

8. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कुलपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर से NEP-2020 से सबंधित पीपीटी प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध किया गया।

9. कुलपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर द्वारा NEP-2020 से सबंधित PPT का प्रस्तुतिकरण किया गया **(संलग्नक–2)**।

   - प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान से लागू करने के संबंध में राजभवन द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा अपनी फाईनल रिपोर्ट तैयार कर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

10. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बैठक के समापन संबोधन में निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

- गत वर्ष प्रदेश में 04 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को NAAC रैंकिंग प्राप्त थी अभी 05 विश्वविद्यालयों को NAAC रैंकिंग प्राप्त हो गई है, तथा अन्य विश्वविद्यालय भी NAAC रैंकिंग प्राप्त करने की दिशा में सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर रहे है, जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में और भी विश्वविद्यालयों को NAAC रैंकिंग प्राप्त हो सकेगी।

- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। पेंशन का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाता है, जिससे विश्वविद्यालयों को आर्थिक भार का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिससे सेवानिवृत कार्मिकों को पेंशन का भुगतान करने से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है।

- निजी महाविद्यालयों को मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार को महाविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता करने के उपरान्त ही मान्यता प्रदान करनी चाहिए। प्रदेश के अनेक निजी महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं हेतु आधारभूत सुविधाएं यथा नियमानुसार प्रर्याप्त शिक्षक/कार्मिक, पीने का स्वच्छ पानी, खेल के मैदान, शौचालयों, कक्षा कक्ष एवं आवश्यक भवन जैसी सुविधाओं का अभाव है।

- विश्वविद्यालयों मे Skill Based शिक्षा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी डिग्री/डिप्लोमा पूर्ण करने के पश्चात बेरोजगार ना रहे, अपनी Skill के आधार पर अपना कोई भी कार्य प्रारम्भ कर जीवनयापन कर सके।

- शिक्षा से संबंधित सभी विभागों को एक ही कैम्पस में लाना चाहिए, जिससे शिक्षा के किसी भी काम के लिए अलग–अलग जगह नहीं जाकर सभी कार्य एक ही कैम्पस में पूर्ण हो सके।

- भारत एक कृषि प्रधान एवं युवा आबादी वाला देश है, वर्तमान में Skill Based पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण काफी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार है, उक्त परिप्रेक्ष्य में तकनीकी व कृषि क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में Skill Based पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता है, जिससे शिक्षित युवाओं को Skill Based पाठ्यक्रम के आधार पर रोजगार मिलना सुगम हो सकेगा।

- विश्वविद्यालयों को सुविख्यात विदेशी शिक्षण संस्थानों के विख्यात विद्वानों के Special Lectures दिलवाने का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित एवं उत्साहित होंगे।

- प्रदेश में जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए, जिससे वर्षों से चली आ रही लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति से छुटकारा मिल सके, पूर्व में दो बार शिक्षा नीति में आंशिक बदलाव किये गये है परन्तु लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है। "आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि देश जब आजाद हुआ तब ब्रिटिश झण्डा उतारकर भारतीय ध्वज फहराया गया, तभी से भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव होना जरूरी था, परन्तु शिक्षा नीति में वह बदलाव नहीं किया गया, जिससे आज भी देश में लार्ड मैकाले की गुलामी की मानसिकता वाली शिक्षा नीति जारी है।"
- देश में शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता एवं शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो सके।

11. सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद प्रस्ताव रखा। अंत में राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन किया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
उपसचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(23)आर.बी./2024/ दिनांक : जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. कुलपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर।
11. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
13. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
14. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।

Sd/–

उप सचिव

राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांकः एफ1(A)(23)आरबी/2024/4005 दिनांकः 24 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. निदेशक (जनजातीय कल्याण) एवं विशिष्ठ सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. परिसहाय, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
5. नियंत्रक, हाउसहोल्ड, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, राजभवन, जयपुर।
7. प्रभारी (IT), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
9. निजी सहायक, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।

उप सचिव

राज्यपाल, राजस्थान

NAAC Review Meeting

17-07-2025

Department of Higher and Technical Education,

Govt. of Rajasthan

Why Assessment and Accreditation by NAAC

- To know strengths, weakness, opportunities and Challenges through review process
- Identification of internal areas of planning and resource allocation
- Continuous improvement
- Accountability of all stake holders
- Initiate innovative and modern methods of pedagogy
- Intra and inter-institutional interactions
- Recognition of peers and Stakeholders

Present Criterion for Accreditation and Weightage

S. No	Criterion	University Weightage	Autonomous Weightage	Affiliated Weightage-UG	Affiliated Weightage-PG
1	Curricular Aspects	150	150	100	100
2	Teaching-learning & Evaluation	200	300	350	350
3	Research, Innovations & Extension	250	150	110	120
4	Infrastructure & Learning Resources	100	100	100	100
5	Student Support & Progression	100	100	140	130
6	Governance, Leadership & Management	100	100	100	100
7	Institutional Values & Best Practices	100	100	100	100
	Total	1000	1000	1000	1000

Background

- **Honourable Governor of Rajasthan** has directed that all state-funded universities in the state must obtain NAAC accreditation at the earliest.
- In line with this, the Department had constituted a mentoring committee vide order dated **10.10.2024**, assigning **four Vice Chancellors** the responsibility of mentoring **two universities each** to expedite the accreditation process.
- Department sought progress reports from all concerned universities vide its order dated 09.04.2025.
- In a follow up, a review meeting was held at Rajbhawan on 16 April 2025.
- Department also organised a review meeting in this regard on 19 May 2025.

Present status regarding NAAC Accreditation

- **NAAC stopped accepting Institutional Information for Quality Assessment (IIQA) after 30th June 2024**.
- Proposed to introduce mechanism comprising:

1. Binary Accreditation (Basic Accreditation), and

2. Maturity-Based Graded Levels (MBGL).

- As per NAAC's **press release dated 10th February 2025**, the **Binary Accreditation** process is expected to commence soon, followed by the MBGL process.

Press Release Main Points

- Institutions that have already submitted their (Institutional Information for Quality Assessment (IIQA) have been directed by NAAC to :-
  - Retain their application validity until the new system is launched.
  - Choose to undergo the existing accreditation mechanism through a **hybrid mode (online and offline)**.
  - Higher Education Institutions (HEIs) in their **first cycle** have been advised to opt for **Basic Accreditation** under the revised structure.

Present Status of State Funded Universities regarding NAAC Accreditation

- **Universities with Valid Accreditation** — **Grade**
  1. Jai Narain Vyas University, Jodhpur — B^{++}
  2. Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur — A
  3. Vardhman Mahaveer Open University, Kota — A
  4. Maharaja Ganga Singh University, Bikaner — C
  5. University of Rajasthan, Jaipur — A^{+}

- **Universities which can be directed to undertake the Accreditation process**
  1. Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
  2. University of Kota, Kota
  3. Haridev Joshi University of Journalism and Mass communication, Jaipur
  4. National Law university, Jodhpur

Present Status of State Funded Universities regarding NAAC Accreditation

Universities not fulfilling the criteria of Regular appointed faculty

1. Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar
2. Raj Rishi Bhartrihai Matsya University, Alwar
3. Govind Guru Tribal University, Banswara and
4. Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur

Universities not fulfilling the minimum criteria of six years of establishment

1. Bhim Rao Ambedkar Law university, Jaipur (2019)
2. M.B.M University, Jodhpur (2021)

Present status Non-Accredited University

Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer

- Going for 3rd cycle of NAAC accreditation
- Filled Annual Quality Assurance Reports (AQARs) for all past years 2016-2025.
- Prepared Institutional Development Plan (IDP) and submitted to Internal Quality Assurance Cell (IQAC).
- Have nominated Criterion Incharges.
- University has expressed its non readiness for the process due to the paucity of required faculty (9 permanent against 182 sanctioned)
- Also mentioned lack of non-teaching human resource.

Present status Non-Accredited University

University of Kota, Kota

- Shall apply for second cycle of NAAC Accreditation
- AQARs have been prepared and submitted on NAAC portal (2018-23)
- AQAR for the year 2023-24 is under process
- Constituted committee in April 2023 for preparation of Self Study Report (SSR)
- Preparations underway as per the 10 points of the proposedBinary Accreditation Guidelines

Present Status of State Funded Universities regarding NAAC Accreditation

National Law University, Jodhpur.

- University has started making all preparation for Accreditation process
- IQAC is making multi-pronged interventions regarding academic reforms and infrastructural development and procurement of Academic data bases.
- Working on expanding and showcasing its specialized strengths as per the NAAC requirements
- Shall be going for accreditation in 2026.

Present status Non-Accredited University

Maharaja Surajmal Brij Universiry, Bharatpur

- Formation of IQAC is under process
- No regular faculty
- In the process of obtaining 12B recognition from UGC
- Has registered on official NAAC portal
- Regular discussions and meetings are being organized regarding accreditation process

Present status Non-Accredited University

Pandit Deen Dayal Shekhawati University, Sikar

- Has submitted non-availability of Teaching Staff
- Accreditation process to be taken up only after the recruitment of regular faculty
- University has informed the mentor VC regarding the above fact.
- Recruitment to various teaching posts in under process

Present status Non-Accredited University

Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication

- IQAC constituted
- Graduation courses introduced from the year 2019
- University to shift to the new campus soon
- Six years mandatory duration for accreditation completed this year only
- University is making required preparations regarding NAAC process
- Made consultations with the mentor VC and working to expedite accreditation process accordingly

Present status Non-Accredited University

Shri Govind Guru Tribal University, Banswara

- Lacks regular faculty
- Applying for 12B recognition. Construction work of five departments mandatory for 12B recognition is going on.
- Planning an online workshop with the mentor Vice Chancellor
- Submitted that NAC accreditation can only be taken up after recruitment of regular staff

Present status Non-Accredited University

Rajrishi Bharithari Matsya University, Alwar

- Lacks sufficient infrastructure
- Construction work is underway
- Non-Availability of Teaching and Non-Teaching staff
- Accreditation to be taken up only after sufficient availability of infrastructure and recruitment of staff.

Road Ahead.....

- Need to strengthen IQACs
- All universities to be directed to fill Annual Quality Assurance Report
- All efforts to be made in accordance with the proposed NAAC accreditation process
- To be instructed for Documenting all the events and progress
- To develop verifiable mechanism regarding procurement of student related information
- To document institutional Best practices with a well defined Vision and Mission
- Work on Green initiatives and SWOC Analysis
- Submit monthly report to mentor VCs and department

Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDP):-

- NEP integrates general and skill education.
- UGC has introduced AEDP program of 1-3 semesters to be incorporated in the curriculum.
- Tool for actual transformation for Higher Education.
- Emphasizes hands on training and experiential learning.
- Collaborate with industries for real-time exposure and on the job training (OJT).
- Increase the employability many folds.
- Allow institutions to become engines of our economic growth.

Thanks

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

Reimagine, Reinvest, Reshape:
Higher Education in Rajasthan in alignment with NEP2020

Presented by:

Prof. Anand Bhalerao
Vice Chancellor

17th July 2025

Committee

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

Hon'ble Governor constituted a committee, comprising following members:

i. **Prof. Anand Bhalerao**
Vice Chancellor, Central University of Rajasthan

ii. **Prof. Manoj Dixit**
Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner

iii. **Dr. Ajeet Kumar Karnatak**
Vice Chancellor, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur,

With the objective to prepare an action plan to implement NEP-2020 in the State Funded Universities of Rajasthan.

Presentation Draft Action Plan

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- Committee met physically/online and prepared a draft report.
- Draft report was presented to Hon'ble Governor (16.04.2025).
- It was decided to prepare a detailed report.

3

Reforms Suggested

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- Curriculum Reforms
- Institutional Reforms
- Examination Reforms
- Accreditation and Ranking
- Research Reforms
- Promotion of Education in Indian Languages
- Faculty Capacity Building
- Institutional Development Plan(IDP)
- Monitoring Cell

4

Curriculum Reforms

- Adoption of NHEQF and NCrF frameworks
- Outcome-based education (OBE)
- Experiential learning
- ME-ME system
- Academic Bank of Credits for flexibility
- Internship
- Skill Development & Vocational Courses
- Online courses from SWAYAM/NPTEL

5

Multiple Entry Multiple Exit (ME-ME)

- Suggestive degrees on Exit after:
  - 1st year: UG Certificate (40 credits, Level 4.5)
  - 2nd year: UG Diploma (80 credits, Level 5)
  - 3rd year: UG Degree (120 credits, Level 5.5)
  - 4-year UG with Research: Honors/Research Degree (160 credits, Level 6)
  - 1st year: PG Diploma (40 credits, Level 6)
  - 2nd year: PG Degrees (80 credits, Level 6.5)
- Equivalence of courses
- Credit based fee structure
- Technological support to facilitate student multiple entry and exit

6

Institutional Reforms

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- End of affiliating culture
- Cluster of Institution
- Autonomy to the Institutions
- Multidisciplinary education hubs to promote innovation, collaboration, and holistic learning
- Consortia to pool resources, share faculty, and offer joint degrees
- Alumni & CSR partnerships

7

Examination Reforms

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- ABC/APAAR ID
- Credit transfer
- Digital Assessment
- Skill-focused assessments
- Uniformity in assessment
- Enhance mobility across institutions

8

Accreditation and Ranking

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- Out of 99 universities in total, 35 have obtained accreditation.
- Among the 32 state-funded universities, six are accredited.
- C. U. of Rajasthan has earned an A++ grade, achieving a CGPA of 3.54.
- Suggested measures include:
- Mandating NAAC accreditation for all institutions.
- Establish IQAC within institutions to facilitate NAAC preparation.
- Provide incentives to institutions securing high NAAC grades (A and above).
- Academic and administrative Audits per two years .
- Hand holding to universities yet to be Accredited. .

9

Research Reforms

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- Set up R&D cells & incubation centers as per UGC norms
- Start-up support through grants and mentoring
- Anusandhan National Research Foundation(ANRF)
- Identifying funding channels at State level
- IPR creation
- Interdisciplinary Research Collaborations

10

Promotion of Education in Indian Languages

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- **Indian Knowledge System(IKS)**
  - **Sanskrit and Prakrit Education**
  - **Archaeology and Cultural Heritage**
  - **Performing Arts and Indian Music**
  - **Indigenous and Endangered Languages**
  - **Yoga and Wellness**
- **Education in Indian Languages**
  - **Books and Study Material in Indian Languages**
  - **Writing Tools in Hindi and Regional Languages**
  - **Government initiatives like the "Bhashini" app**

11

Faculty Capacity Development

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- **Training Need Analysis (TNA)**
- **Collaboration with National Institutes (NITTTR Bhopal, Chandigarh, Chennai,) for training in pedagogy, curriculum innovation.**
- **Lifelong learning for Adaptability to emerging trends.**
- **Development of Internal quality assessment**
- **Training be as a part of performance appraisal**

12

Institutional Development Plan(IDP)

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- **Identify next five-year plan**
- **Goals to make HEIs more flexible and globally competitive**
  - **Develop annual capacity-building plans**
  - **Promote digitalization**
  - **Foster skills, employability, and global mobility**
  - **Set measurable goals with regular reviews**

13

Institutional Development Plan(IDP)

(CGPA-3.54)
(Category-I University)

- **SWOC Analysis**
- **Portfolio Mapping: It helps universities evaluate and organize programs based on performance and potential.**
- **SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound targets)**
- **Aligning resource allocation and its execution**
- **Maintaining proper feedback, review and continuous evaluation**

14

Monitoring Cell

- **To establish Monitoring Cell at State level.**
- **Monitoring cell comprising of senior administrator/high court judges as chairman and senior academicians to regularly monitor the progress at least twice a year.**
- **To Prepare a state-level roadmap to move a multidisciplinary research-oriented learning ecosystem.**
- **Revise Acts and Statutes to enable autonomy and flexibility, uniform for all State Universities.**

15

THANK YOU

16